राष्ट्रीय संस्करण

ट्रंप के वित्तीय रिकॉर्ड मामलों की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

>> 13

वर्ष 3 अंक 187

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 15 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

कभी गरजती थीं बंदूकें, अब फसल लहलहाती है...

औरैया : उप्र औरैया जिले का का मई मानपुर गांव। जहां कभी बंदूकें गरजती थीं, वहां अब समृद्धि की फसल लहलहा रही है। शराब की जगह दूध की नदियां बह रही हैं। अब स्कूलों में सन्नाटा नहीं ककहरा गूंजता है। यह संभव हुआ, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन से। (पेज-11)

रविवार विशेष

बनारस की गंगा आरती का दीदार करा रहा 'डिंगी'

वाराणसी : आइआइटी बीएचयू के पूर्व छात्र का स्टार्टअप 'डिंगी एप' काशी में चर्चा में है। देश-विदेश के सैलानियों को यहां गंगा में नौकाविहार के लिए जहां बुकिंग का आसान प्लेटफार्म मुहैया हो गया है, वहीं नाविकों को बेहतर रोजगार। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

सीबीआइ ने लीला सैमसन के खिलाफ मामला दर्ज किया

नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने चेन्नई स्थित कलाक्षेत्र फाउंडेशन के कुथंबलम सभागार के पुनरुद्धार की 7.02 करोड़ रुपये की परियोजना में कथित अनियमितताओं के मामले में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना लीला सैमसन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पद्मश्री से सम्मानित सैमसन संगीत नाटक अकादमी और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

पीएसए के तहत मार्च तक टली फारूक अब्दुल्ला की रिहाई

श्रीनगर : नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर के सांसद डॉ. फारूक अब्दुल्ला की रिहाई फिलहाल टल गई है। सामान्य हालात में अब वह अगले तीन माह तक रिहा नहीं होंगे, क्योंकि जम्मू-कश्मीर सरकार ने जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत उनकी कैद को फिर तीन माह के लिए और बढ़ा दिया है। जन सुरक्षा अधिनियम 1978 को डॉ. फारूक के पिता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ही लागू किया था।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

जीएसटी कंपेंसेशन पर बढ़ रही राज्यों की नाराजगी

नई दिल्ली : जीएसटी कंपेंसेशन (वस्तु एवं सेवाकर क्षतिपूर्ति) के भुगतान में देरी को लेकर राज्यों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। अगले सप्ताह होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। साथ ही राज्य अब केंद्र सरकार पर कंपेंसेशन की अवधि को पांच साल और बढ़ाने का दबाव बना सकते हैं। राज्यों का कहना है कि कंपेंसेशन की अवधि 2021-22 में समाप्त हो जाएगी, लेकिन तब तक रेवेन्यू (राजस्व) वृद्धि की अपेक्षित रफ्तार हासिल होने की कोई उम्मीद नहीं है।

केरेबियाई चुनौती
पहला वनडे
भारत vs वेस्टइंडीज
दोपहर 1:30 बजे से
स्थान : चेन्नई
प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

नमामि गंगे से फूटेगी अब 'अर्थ' की धारा : मोदी

समीक्षा बैठक ▶ राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में खींचा आय का खाका

परिषद हुई और मजबूत, मिला सभी निर्णय लेने का अधिकार

जागरण संवाददाता, कानपुर

'नमामि गंगा' के तहत हुए कार्यों की समीक्षा करने शनिवार को कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अविरल-निर्मल गंगा के सहारे विकास का खाका खींचा, बल्कि यह भी कहा कि आने वाले दिनों में यह योजना आय का सबसे बड़ा जरिया बनने की जा रही है। उन्होंने कहा-'नमामि गंगे की धारा अब अर्थ गंगा की ओर मुड़ने जा रही है।' स्पष्ट खाका भी खींचा कि अविरल-निर्मल धारा कैसे किसानों और सामान्य जनों के लिए आय का बड़ा साधन बनेगी।

प्रधानमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में हुई राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में अब तक हुए विकास कार्यों की पूरी जानकारी ली और जीरो बजट खेती, ईको-एडवेंचर टूरिज्म, रिवर फ्रंट बेसिन का विकास और डॉल्फिन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि आय का साधन बढ़ाने के लिए गंगा के किनारे फलदार वृक्ष लगाएं, नर्सरी बनाएं। इसमें महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों व पूर्व सैनिक संगठनों को प्राथमिकता दें। गंगा किनारे एडवेंचर स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, वाकिंग पाथ-वे की व्यवस्था करें। गंगा में जलयान यानी क्रूज टूरिज्म का रोमांच दें।

प्रधानमंत्री ने परिषद को और मजबूत करते हुए उसे गंगा व सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए सभी निर्णय लेने के अधिकार दिए। कहा, सभी विभाग और मंत्रालय गंगा केंद्रित सोच के साथ एकजुट होकर कार्य करेंगे। नीति आयोग व जलशक्ति मंत्रालय जिलावार निगरानी करेगा। उन्हें डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए हर रोज शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का डाटा मिलेगा। सीएसए में तय समय से डेढ़ घंटा अधिक रुके पीएम ने कहा, गंगा का कायाकल्प करना वर्षों की चुनौती है। 2014 में नमामि गंगे शुरू होने के बाद सरकार ने बहुत कुछ किया है। पेपर मिलों को जीरो डिस्चार्ज किया गया है तो टेनरी के प्रदूषण में भी कमी आई है। अभी भी काफी कुछ करना बाकी है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कानपुर में वोट से भ्रमण कर गंगा का हाल जाना। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी (योगी के पीछे), उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत (बाएं) भी साथ थे। मो. आरिफ

मोटर बोट से गंगा में भ्रमण

प्रधानमंत्री ने मोटर बोट से गंगा का भ्रमण किया। वह सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ अटल घाट से 128 साल पुराने सीसामऊ नाला तक गए और निरीक्षण किया।

20 हजार करोड़ खर्च करने वाली पहली सरकार

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन पांच राज्यों से गंगा होकर बहती है, वहां जल प्रवाह को ठीक बनाए रखने के लिए 2015-20 के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करने वाली यह पहली केंद्र सरकार है। अब तक नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए 7,700 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। उन्होंने जिला गंगा समितियों को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने गंगा को साफ करने के लिए क्लीन गंगा फंड बनाया हुआ है। इसमें व्यक्तिगत, एनआरआइ, कारपोरेट संस्थाएं योगदान कर सकती हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 2014 से अब तक मिले उपहारों की नीलामी और सियोल शांति पुरस्कार से प्राप्त धनराशि से 16.53 करोड़ रुपये इस फंड में दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रस्तुत की कार्यों की रिपोर्ट पेज>>5

असम शांत, बंगाल में बढ़ा बवाल

सीएए के विरोध में बंगाल में दूसरे दिन भी जमकर उपद्रव व आगजनी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

▶ ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ कई बसों में भी लगाई आग

▶ गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू में ढील, नगालैंड में बंद का आयोजन

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध करने में आगे रहे पूर्वोत्तर के राज्यों में शनिवार को शांति रही। इसी के चलते असम के गुवाहाटी व डिब्रूगढ़ और मेघालय की राजधानी शिलांग में कर्फ्यू में ढील दी गई। नगालैंड में छह घंटे का बंद आयोजित किया गया। जबकि बंगाल दूसरे दिन भी जलता रहा। शुक्रवार की घटनाओं से रेल प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया, लिहाजा दूसरे दिन भी रेलवे को ही सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने कई बसों को आग लगाने के अलावा रेलवे स्टेशनों पर आगजनी की, फर्नीचर को ट्रैक पर डालकर आग लगा दी, टिकट काउंटरों पर तोड़फोड़ और लूटपाट की, खाली खड़ी चार ट्रेनों और मालगाड़ी के इंजन को आग के हवाले कर दिया गया। जान बचाने के लिए रेल कर्मचारी स्टेशनों को छोड़कर भाग खड़े हुए। लिहाजा 40 से अधिक ईएमयू और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद कर दिया गया। सात ट्रेनों को रास्ते में ही समाप्त कर दिया गया। जबकि पांच ट्रेनों को मार्ग बदलकर चलाया गया। उधर, नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में पांच जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है और सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं।

सूत्रों के अनुसार, बंगाल में प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन अंतर्गत कई स्टेशनों को निशाना बनाया। मुर्शिदाबाद के सुजनीपाड़ा स्टेशन को तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। कृष्णपुर स्टेशन पर खाली खड़ी चार ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। लालगोला, जियागंज स्टेशनों में भी तोड़फोड़ की गई। स्टेशनों के फर्नीचर को ट्रैक पर डालकर आग लगा दी गई, इससे लालगोला-कृष्णानगर सेक्शन पर संचालन पूरी तरह ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों ने दूसरे दिन भी बेलडांगा स्टेशन पर तोड़फोड़ और आगजनी की। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी को भी आग लगा दी गई। हारुआ रोड स्टेशन के पास और सोनदलिया-लेबुतला स्टेशन के बीच लेवल क्रासिंग तोड़ दिया गया। ट्रेनों पर भी जमकर पथराव किया गया। भीड़ के तेवर देख आरपीएफ और जीआरपी के साथ ही रेल कर्मचारी भी भाग खड़े हुए।

हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन पर भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। भीड़ ने सांकराइल स्टेशन पर स्टेशन मास्टर कक्ष के पैनल बोर्ड, टिकट काउंटर, प्लेटफार्म और लेवल क्रासिंग गेट को तोड़ दिया। टिकट काउंटरों पर लूटपाट व आगजनी भी की गई। नलपुर व चंगेल स्टेशन पर भी तोड़फोड़ की। बाउरिया स्टेशन पर मालगाड़ी के इंजन में आग लगा दी गई। जगह-जगह रेल पटरी पर टायर जलाकर ट्रेन संचालन ठप कर दिया गया। मौके पर पहुंचे रेल कर्मचारियों को पीटा। मालदा डिवीजन के हरिश्चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई।

प्रदर्शनकारियों ने बसों और अन्य वाहनों को भी निशाना बनाया। कोना एक्सप्रेस वे पर 25 सरकारी व निजी बसों को आग लगा दी गई। मालदा व मुर्शिदाबाद जिलों में कई बसों को आग लगाए जाने की खबर है। टोल प्लाजा को भी आग लगा दी। यहां यात्रियों को जबरन बस से उतार दिया गया। जिले में पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। हावड़ा, दोमजुर बगनान के साथ ही बीरभम जिले में टायर जलाकर सड़कों को ब्लॉक कर दिया और कई दुकानों में भी आग लगा दी।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शनिवार को हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर जमकर पथराव किया और कई जगह आगजनी की। पथराव से बचने की कोशिश करते सुरक्षा बल। प्रेट्र

राजनाथ बोले, शरणार्थियों को पक्की नागरिकता देगी सरकार पेज>>5
राष्ट्रीयता का राष्ट्र धर्म ! (मुद्दा) पेज>>7

उन्नाव के बाद अब फतेहपुर में दरिंदगी, दुष्कर्म कर युवती को केरोसिन डाल कर जलाया

जागरण संवाददाता, फतेहपुर

▶ पड़ोसी ने दिया घटना को अंजाम, युवती 90 फीसद झुलसी

▶ जिला अस्पताल में बयान लेने के बाद किया गया कानपुर रेफर

उत्तर प्रदेश में दरिंदगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्नाव के बाद अब फतेहपुर में दरिंदगी की वारदात सामने आई है। शनिवार सुबह हुसेनगंज क्षेत्र के एक गांव में दरिंदे ने घर में घुसकर 18 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर केरोसिन उड़ेलकर जिंदा जलाने की कोशिश की। चीखती युवती बाहर की ओर भागी। पड़ोसियों ने आग बुझाकर उसे सदर अस्पताल पहुंचाया। 90 फीसद झुलसी पीड़िता को हैलट अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गया। एडीजी सुजीत पांडेय समेत कई अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया।

सुबह करीब नौ बजे पड़ोस में रहने वाला चाचा घर में युवती को अकेला पाकर घुस आया और दुष्कर्म किया। युवती ने जब स्वजनों को जानकारी देने की बात कही तो आरोपित ने उसके शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। वह चीखते हुए घर के बाहर भागकर आ गई। आग बुझाने के बाद पड़ोसी ने पास के नर्सिंगहोम में उसका प्राथमिक उपचार कराया। बाद में सदर अस्पताल लेकर आए। डॉ. नरेश विशाल ने बताया कि युवती 90 फीसद से अधिक झुलस गई है। हालत बेहद गंभीर होने पर उसे कानपुर भेज दिया गया। पीड़िता के भाई ने थाने में तहरीर देकर बताया कि स्वजन मजदूरी करने गए थे। घर में बहन अकेली थी, तभी पड़ोसी घुस आया और दुष्कर्म कर उसे जला दिया। एसपी के मुताबिक, आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म कर जानलेवा हमले के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। देर शाम गांव पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।

ट्रॉमा सेंटर में मजिस्ट्रेटी बयान : नायब तहसीलदार संतराज ने सीओ सिटी कपिलदेव मिश्र, महिला थाना प्रभारी नमिता सिंह आदि की मौजूदगी ट्रॉमा सेंटर में युवती के बयान दर्ज किए। पीड़िता ने बयान में कहा कि युवक ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी।

प्रेम प्रसंग की बात

डीएम संजीव कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता व आरोपित के बीच दो साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों परिवारों के बीच पंचायत में युवक को युवती की शादी होने तक गांव से बाहर रहने की हिदायत दी गई थी। जिससे क्षुब्ध होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है।

वाहन चालकों को नेशनल हाईवे पर फास्टैग से एक माह की राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ टोल प्लाजा की एक-चौथाई लेन में चालकों से कैश भी होगा स्वीकार

▶ फास्टैग की कमी को देखते हुए सरकार ने एनएचएआइ के आग्रह पर दी राहत

सरकार ने वाहन चालकों को फास्टैग खरीदने और बिना जुर्माने के टोल प्लाजा से निकलने के लिए 30 दिनों की मोहलत दे दी है, लेकिन एनएच पर स्थित सभी टोल प्लाजा की तैयारी के लिहाज से फास्टैग का उपयोग रविवार से अनिवार्य कर दिया गया है। फास्टैग मिलने में हो रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने चालकों को एक माह की मोहलत दी है। इस दौरान वे टोल प्लाजा की चौथाई लेन में कैश भुगतान कर गुजर सकेंगे। टोल प्लाजा को रविवार से कम से कम तीन-चौथाई लेन में फास्टैग की सुविधा अनिवार्य रूप से मुहैया करानी होगी।

सरकार ने एनएचएआइ से कहा है कि वह एक माह तक कम से कम एक-चौथाई लेन को हाइब्रिड लेन में बदलने की व्यवस्था करे। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी टोल प्लाजा में आठ लेन हैं तो वहां दो लेन में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के अलावा कैश भुगतान भी स्वीकार होंगे। जहां 12 लेन हैं वहां तीन लेन कैश के लिए भी खुली होंगी। अभी तक केवल एक लेन में ही कैश भुगतान की सुविधा होने से लंबी कतारें लग जाती थीं। सड़क मंत्रालय ने एनएचएआइ से कहा है कि वाहन चालकों को सुविधा देने के साथ-साथ उसका प्रयास हाइब्रिड लेन की संख्या को कम से कम रखने का होना चाहिए, ताकि लोग जल्दी से जल्दी फास्टैग लेने का प्रयास करें। किसी भी हालत में फास्टैग लेन 75 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिए।

इससे पहले एनएचएआइ ने मुश्किलें गिनाते हुए सड़क मंत्रालय से फास्टैग अनिवार्यता की तारीख बढ़ाने अथवा 45 दिनो तक एक से अधिक लेन को हाइब्रिड लेन में बदलने की अनुमति मांगी थी। एनएचएआइ का कहना था कि देश में चिप का पर्याप्त उत्पादन नहीं होने से फास्टैग की आपूर्ति काफी कम है। बीती छह दिसंबर तक देश में रोजाना 1.96 लाख फास्टैग जारी हो रहे थे। फास्टैग में आयातित चिप के उपयोग और उसकी बढ़ती मांग को देखते हुए एनएचएआइ ने पांच-छह दिसंबर को टैग निर्माताओं तथा बैंकों के साथ स्थिति की समीक्षा की। अभी फास्टैग निर्माताओं की कुल दैनिक उत्पादन क्षमता 50 हजार टैग बनाने की ही है। निर्माताओं के पास पहले से 18 लाख फास्टैग आपूर्ति के ऑर्डर पड़े हुए हैं। एनएचएआइ के अनुरोध पर सड़क मंत्रालय ने फास्टैग अनिवार्यता की तारीख को पहली दिसंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर किया था।

राहुल बोले, मैं सावरकर नहीं, शिवसेना ने कहा-मत करें अनादर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ बोले-माफी नहीं मांगूंगा, मोदी और अमित शाह को मांगनी चाहिए माफी

▶ दोनों नेताओं पर लगाया अर्थव्यवस्था तबाह करने का आरोप

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं मर जाऊंगा, पर माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा है, सच कहा है। वैसे भी मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। माफी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी अमित शाह को मांगनी चाहिए, जिन्होंने देश की मजबूत अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। एक दिन पहले ही रेप इन इंडिया बयान पर घिर चुके राहुल गांधी द्वारा इस तरह सावरकर का नाम लिए जाने का शिवसेना ने तत्काल प्रतिवाद किया। हाल ही में कांग्रेस की सहयोगी बनी पार्टी ने कहा कि हिंदुत्व के प्रतीक का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। शिवसेना के नेता संजय राउत ने ट्वीट किया कि वीर विनायक दामोदर सावरकर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए देवतुल्य हैं। हम गांधी और नेहरू का सम्मान करते हैं। आपको सावरकर का अपमान नहीं करना चाहिए।

कांग्रेस की भारत बचाओ रैली को संबोधित करते राहुल गांधी। ध्रुव कुमार

कांग्रेस की भारत बचाओ रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, भाजपा के लोग उनके बयान पर उन्हें माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, लेकिन, वह कभी माफी नहीं मांगेंगे। यहां बता दें कि राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान से खफा भाजपा ने शुक्रवार को संसद के भीतर और बाहर माफी मांगने की मांग की। राहुल ने कहा, पूरी दुनिया पहले भारत की मजबूत अर्थव्यस्था की ओर देखती थी, लेकिन, पीएम मोदी की चोट से अर्थव्यस्था अब तक उबर नहीं पाई है। जीडीपी चार फीसद पर पहुंच गई है। हिंदुस्तान के सारे दुश्मन चाहते थे, कि इसकी अर्थव्यवस्था को नष्ट किया जाए, लेकिन, वह काम दुश्मन ने नहीं, मोदी ने किया है। राहुल ने कहा, यह सरकार एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ा रही है। पूरे पूर्वोत्तर की स्थिति खराब है। कार्यकर्ताओं के हौसले को बढ़ाते हुए कहा, इस देश को डराया और दबाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर और शेरनियां है, वह किसी से डरने वाला नहीं है।

> सावरकर का नाम राष्ट्र और स्वयं के बारे में गौरव को दर्शाता है। गांधी और नेहरू की तरह सावरकर ने भी देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इन सबका देवों की तरह सम्मान किया जाना चाहिए। इससे कोई समझौता नहीं होगा।
>
> **- संजय राउत, शिवसेना सांसद**

भाजपा ने कहा, इनका नाम तो राहुल जिन्ना होना चाहिए

नई दिल्ली, प्रेट्र : राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा, कांग्रेस नेता के लिए उपयुक्त नाम 'राहुल जिन्ना' है, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उन्हें पाक के संस्थापक का उत्तराधिकारी बनाती है। ज्ञात हो, भाजपा सावरकर को काफी ऊंचा दर्जा देती है, लेकिन, विरोधी सावरकर पर ब्रिटिश शासन से माफी मांगने का आरोप लगाते हैं।

देश की आत्मा को तार-तार कर देगा नागरिकता कानून : सोनिया पेज>>3

इनसे मिलिए

22 साल के हसन सफिन 23 दिसंबर को संभालने जा रहे जामनगर एएसपी का पदभार, गुजरात के बनासकांठा में हीरा तराशने के कारखाने में श्रमिक हैं हसन के माता-पिता, बेटे की पढ़ाई में बाधा न आए इसलिए मां ने रेस्त्रां में खाना बनाने का भी किया काम

हीरा तराशने वाले माता-पिता का बेटा निकला कोहिनूर

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

बनासकांठा (गुजरात) निवासी 22 वर्षीय हसन सफिन 23 दिसंबर को जामनगर में सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के रूप में पदभार संभालने जा रहे हैं। देश के सबसे युवा आइपीएस अधिकारी हसन का कहना है कि देश और समाज की सेवा में हरसंभव योगदान उनकी प्राथमिकता है, जिससे प्रेरित होकर ही उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा को करियर के रूप में अपनाया।

गत वर्ष संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल करने वाले सफिन की इस कामयाबी के पीछे उनके माता-पिता के कठोर संघर्ष का योगदान रहा है। बनासकांठा के पालनपुर क्षेत्र के गांव कणोदर में सफिन का घर है। यहीं उनकी परवरिश हुई। पिता मुस्तफा हसन और मां नसीमबानु नजदीक स्थित एक कारखाने में हीरे तराशने का काम करते। हसन बचपन से मेधावी थे, लिहाजा माता-पिता ने इस बात का हरसंभव प्रयास किया कि बेटे की शिक्षा में गरीबी आड़े न आने पाए। जब पैसों की कमी पड़ने लगी तो मां नसीमबानु ने दोहरी भूमिका निभाई। रेस्त्रां और विवाह समारोह आदि में रोटी-पूड़ी बेलने का काम भी करने लगीं। इधर, सफिन ने भी जमकर मेहनत की। माता-पिता की मेहनत को जल्द से जल्द सफलता में परिणत करने का जज्बा उनके लिए प्रेरणा का काम कर रहा था। सहायक पुलिस अधीक्षक, जामनगर का पदभार संभालते हुए वह भारत में सबसे कम उम्र के आइपीएस अधिकारी होंगे।

सफिन कहते हैं, मैंने आइएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) को लक्ष्य बनाया था, लेकिन 570वीं रैंक आई और आइपीएस का विकल्प सामने था। मैं दोबारा परीक्षा देकर रैंक सुधारने के बारे में सोच सकता था, लेकिन फिर तय किया कि अब आइपीएस के रूप में ही देश और समाज की सेवा करूंगा...। वह बताते हैं कि बचपन में अपनी मौसी के साथ एक स्कूल में गए थे, वहां समारोह में पहुंचे कलेक्टर की बातें सुन और उनका रुतबा देख बेहद प्रभावित हुए। मौसी से पूछा कि यह कौन है, तो उन्होंने बताया कि यह आइएएस अधिकारी हैं और जिले के मुखिया हैं। उसी दिन उन्होंने आइएएस अधिकारी बनने की ठान ली। गांव कणोदर में प्राथमिक शिक्षा के बाद हसन ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पास की और पढ़ाई के लिए सूरत चले गए। फिर स्नातक के बाद गुजरात लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर जिला रजिस्ट्रार बन गए, लेकिन मन में आइएएस या आइपीएस बनने की इच्छा थी। गुजरात कैडर से आइपीएस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब वह पदभार ग्रहण करेंगे।

सफिन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं, फेसबुक पेज पर उनके करीब 80 हजार से अधिक फॉलोअर हैं। पिता मुस्तफा और मां नसीमबानु बेहद खुश हैं, कहते हैं बेटे ने जो ठाना वह कर दिखाया। हमारा सपना साकार हो गया।

हसन सफिन। (सौ. परिजन)

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति पर छात्रों ने किया हमला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ कार का शीशा तोड़ा, टीचर फेडरेशन ने की जांच की मांग, छात्र संघ ने कहा-सिर्फ छात्रावास के मुद्दे पर किया था सवाल

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति पर शनिवार को छात्रों ने हमला किया। जेएनयू के कुलपति प्रो. एम. जगदीश कुमार ने दावा किया है कि उन पर 10 से 15 छात्रों ने हमला किया। जेएनयू टीचर फेडरेशन (जेएनयूटीएफ) ने इस मामले की प्रशासनिक जांच और आरोपितों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं जेएनयू छात्र संघ ने कुलपति के आरोपों से इन्कार किया है।

कुलपति ने कहा, शनिवार को वह जेएनयू के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में कुछ काम के सिलसिले में गए थे। वहां 10 से 15 छात्रों ने उन्हें घेरकर गिराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि छात्र उन पर हमला करना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी ने किसी तरह उन्हें बचाया। इस दौरान उनकी कार का शीशा भी तोड़ दिया गया। जेएनयूटीएफ से जुड़े शिक्षकों ने कहा है कि कुलपति के साथ छात्रों द्वारा किए गए हमले की हम निंदा करते हैं। कुलपति की कार के शीशे भी छात्रों ने ही तोड़े हैं। उनके कार्यालय के गेट को भी तोड़ा गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को जेएनयू के कुलपति, रजिस्ट्रार को सुरक्षा देने के लिए निर्देश दिए हैं। पुलिस इन्हें सुरक्षा मुहैया कराए।

वहीं छात्र संघ ने आरोपों से इन्कार करते हुए कहा कि कुलपति स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में पहुंचे थे। कुछ छात्रों ने उनसे छात्रावास के मुद्दे पर सवाल किया तो वह बिना जवाब दिए ही वहां से चल दिए। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि चुनाव के जरिये चुने गए छात्र संघ के प्रतिनिधियों से छात्रावास के मुद्दे पर कुलपति बात करें।